बढ़ेंगे दाम पर नहीं पूरे होंगे अरमान!

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 11 अक्टूबर

...गन्ना किसानों का मामला

- चुनावों के मद्देनजर यूपी सरकार बढ़ा सकती है गन्ने के दाम
- लेकिन घाटे में चल रहीं चीनी मिलें भुगतान में रह सकती हैं नाकाम
- पिछले साल के बकाये का भी नहीं हुआ भुगतान

अगले साल लोकसभा चुनावों को देखते हुए किसानों को भले ही गन्ने की अधिक कीमत मिल जाए, बावजूद इसके उनकी हालत सुधरने के बजाय और खराब हो सकती है। दरअसल उत्पादन लागत से कम पर चीनी बेचने के कारण मिलें किसानों का पूरा भुगतान करने में नाकाम रही हैं और ये मिलें घाटे की चपेट में हैं। ऐसे में चालू चीनी वर्ष में गन्ने की कीमत और बढ़ने पर मिलें पूरा गन्ना खरीद पाएंगी और किसानों को इसका पूरा भुगतान कर पाएंगी, इसे लेकर संदेह खड़ा हो रहा है। जानकार बताते हैं कि मिलों के लिए पूरा भुगतान कर पाना और पूरी क्षमता के साथ चीनी का उत्पादन कराना इस वर्ष काफी मुश्किल लगा रहा है।

चीनी उद्योग के जानकारों के मुताबिक हरियाणा सरकार द्वारा चालू पेराई सत्र में गन्ने का दाम 290 से 301 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर भी गन्ने की कीमत इससे ज्यादा बढ़ाने का दबाव है। चुनावों को देखते हुए राज्य सरकार राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) 30 से 40 रुपये बढ़ाकर अग्रिम किस्म के लिए 320-330 रुपये और सामान्य किस्म के लिए 310-320 रुपये कर सकती है।

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते हैं कि चीनी मिलें घाटे का हवाला देकर सरकार पर गन्ने की कीमत 40 से 50 रुपये तक घटाने का दबाव डाल रही हैं। लेकिन डीजल समेत अन्य खर्चे बढ़ने से किसानों की भी लागत बढ़ी है। ऐसे में गन्ने की कीमत कम से कम 40 रुपये बढ़नी चाहिए। किसानों के एक अन्य संगठन ने एसएपी 327 रुपये करने की मांग की है।

वर्तमान चीनी मूल्य पर मिलों को 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है। जिससे मिलें पेराई वर्ष 2012-13 में किसानो को करीब 2500 करोड़ रुपये का भुगतान करने में नाकाम रही हैं। उद्योग का दावा है कि मिलों को बीते दो साल में करीब 4,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। चीनी कारोबारी सुधीर भलोटिया कहते हैं कि इन हालात में गन्ने की कीमत 40 रुपये बढ़ने पर मिलों को 400 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त घाटा होगा। ऐसे में चीनी के दाम बढ़ना मुश्किल है। मसलन 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल के घाटे में आगे भी मिलों को गन्ना किसानों का पूरा भुगतान करने मुश्किल होगी। जाहिर है गन्ने की अधिक कीमत के बाद भी किसानों पर गिर सकती है गाज।

Business Standard
12/10/13